संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32)

न्यायिक अभिलेख (Writs) **बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeus Corpus)** **परमादेश (Mandamus)**

भारतीय संविधान

*मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है

*किस अधिकार के माध्यम से मूल अधिकार सुनिश्चित किए गए

*व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है

*किस याचिका का शाब्दिक अर्थ 'हम आदेश देते हैं' होता है

*किस याचिका का शाब्दिक अर्थ 'हम आदेश देते हैं' होता है

*अनुच्छेद 32 किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है

*कौनसे मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं

बस नाम ही काफी है STUDY 91 India's Largest E-Learning Platform

DAY-165

4921-4950

Foundation Batch

Call Us Now 7007734525, 9455069191

बस नाम ही काफी है STUDY 91 India's Largest E-Learning Platform

History

Modern

Geography

Polity

New

Science

Economics

Hindi

Environment

New

UP Special

- किस अधिकार के माध्यम से मूल अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं →

  मूल अधिकार → अधिकार-स्रोत; भाग-III; अनु-12-35

  संवैधानिक उपचारों का अधिकार → अनु. 32

- संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है →

  अनु. 32 → रिट

  (1) बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) (2) परमादेश (मैंडमस) (3) अधिकार-पृच्छा (4) उत्प्रेषण (5) प्रतिषेध

- बी. आर. अंबेडकर ने किस अधिकार को "संविधान का हृदय एवं आत्मा" की संज्ञा दी थी → अनु. 32 → संवैधानिक उपचारों का अधिकार

DAY-165

4921-4950

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32)

भारतीय संविधान

- कौन-सा न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है → सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) → अनु. 32

- कौन-सा न्यायालय मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य को लेकर भी रिट जारी कर सकता है → हाई कोर्ट (उच्च न्यायालय) → अनु. 226

- व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन-सी रिट दायर की जा सकती है → बन्दी प्रत्यक्षीकरण

DAY-165

4921-4950

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32)

भारतीय संविधान

- मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है →
  - हनन / उल्लंघन
  - * उच्चतम न्यायालय
  - * उच्च न्यायालय
- किस वर्ष तक केवल कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास उच्च न्यायालय को ही रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त था → 1950 तक
- कौन-सा अनुच्छेद अब सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है → अनु. 226

- जब निरूद्ध व्यक्ति न्यायालय की अधिकारिता के भीतर नहीं है तो कौन सी रिट जारी नहीं की जा सकती → नहीं जारी किया जा सकता → बंदी प्रत्यक्षीकरण
  गिरफ्तार
- जब निरूद्ध व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया है तो कौन सी रिट जारी नहीं की जा सकती → बन्दी प्रत्यक्षीकरण
- किसी अभिलेख न्यायालय अथवा संसद द्वारा अवमानना के लिए कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए कौन सी रिट जारी नहीं की जा सकती → बन्दी प्रत्यक्षीकरण & परमादेश

- किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है → बंदी प्रत्यक्षीकरण

  (कैदी — जेल में बंद व्यक्ति; जब दोषसिद्ध न हुआ हो, तभी)

- किसी मामले में न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के उद्देश्य को शारीरिक स्वतंत्रता के साथ-साथ मानवीय सुरक्षा भी बताया → सुनील बत्रा बनाम दिल्ली (1978)

- न्यायालय किस रिट द्वारा गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति से गिरफ्तार किए जाने का कारण पूछता है → बन्दी प्रत्यक्षीकरण

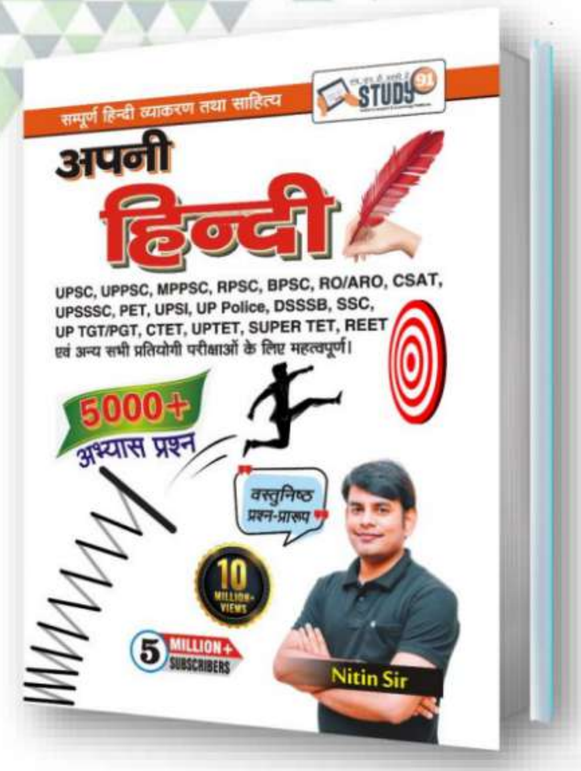
सम्पूर्ण हिन्दी व्याकरण तथा साहित्य
अपनी
हिन्दी
UPSC, UPPSC, MPPSC, RPSC, BPSC, RO/ARO, CSAT, UPSSSC, PET, UPSI, UP Police, DSSSB, SSC, UP TGT/PGT, CTET, UPTET, SUPER TET, REET एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण।
5000+ अभ्यास प्रश्न
वस्तुनिष्ठ प्रश्न-प्रारूप
10 MILLION+ VIEWS
5 MILLION+ SUBSCRIBERS
Nitin Sir

5 MILLION+ SUBSCRIBERS
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित
अपनी हिन्दी 1
RO/ARO
प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा
3000 सवाल
500-500 सवालों के साथ प्रैक्टिस
विलोम शब्द
पर्यायवाची शब्द
विशेषण-विशेष्य
तत्सम-तद्भव शब्द
वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द
वर्ष 2001 से अद्यतन
Nitin Sir

5 MILLION+ SUBSCRIBERS
THINK
Static GK
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण
100+ महत्वपूर्ण टॉपिक
हर समस्या के 2 समाधान हैं।
भाग लो या भाग लो
Run Away or Participate
Nitin Sir

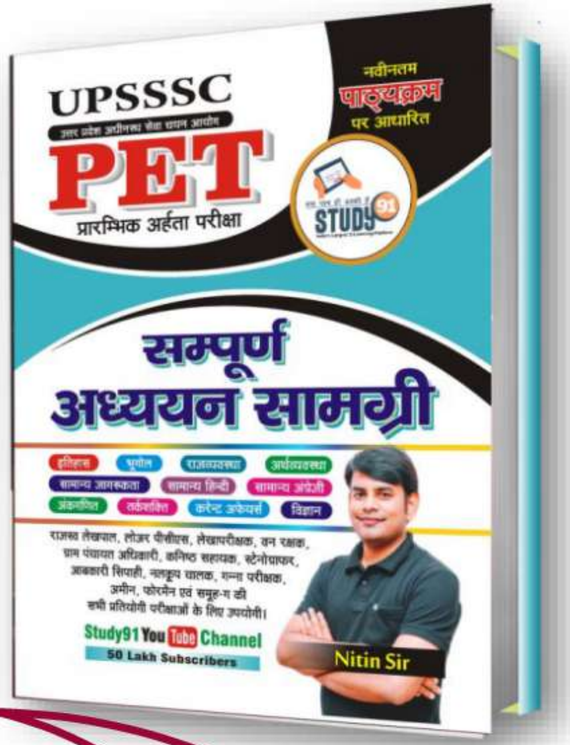
UPSSSC
PET
प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा
नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित
सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री
इतिहास
भूगोल
राजव्यवस्था
अर्थव्यवस्था
सामान्य जागरूकता
सामान्य हिन्दी
सामान्य अंग्रेजी
अंकगणित
तर्कशक्ति
करेंट अफेयर्स
विज्ञान
Study91 You Tube Channel
50 Lakh Subscribers
Nitin Sir

UPSSSC
PET
प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा
नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित
प्रैक्टिस सेट
इतिहास
भूगोल
राजव्यवस्था
अर्थव्यवस्था
सामान्य जागरूकता
सामान्य हिन्दी
सामान्य अंग्रेजी
अंकगणित
तर्कशक्ति
करेंट अफेयर्स
विज्ञान
Study91 You Tube Channel
50 Lakh Subscribers
Nitin Sir

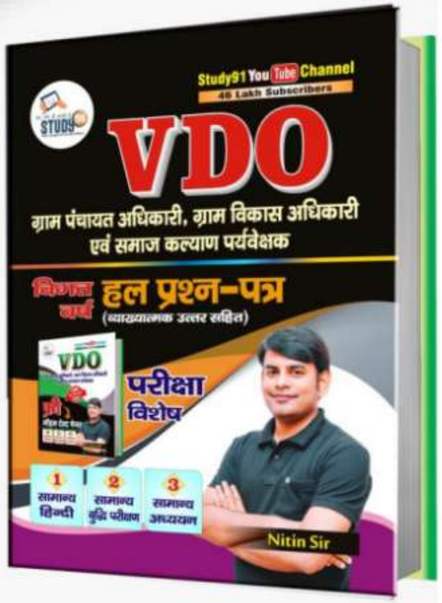
Study91 You Tube Channel
46 Lakh Subscribers
VDO
ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी
एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक
विगत वर्षों हल प्रश्न-पत्र
(व्याख्यात्मक उत्तर सहित)
परीक्षा विशेष
1 सामान्य हिन्दी
2 सामान्य बुद्धि परीक्षण
3 सामान्य अध्ययन
Nitin Sir

Study91 You Tube Channel
46 Lakh Subscribers
VDO
ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी
एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक
NOT FOR SALE
फ्री
मॉडल टेस्ट पेपर
1 सामान्य हिन्दी
2 सामान्य बुद्धि परीक्षण
3 सामान्य अध्ययन
Nitin Sir

Call us now!
7007734525
Fast & Free
DELIVERY

- किस याचिका का शाब्दिक अर्थ 'हम आदेश देते हैं' होता है → परमादेश

बंदी प्रत्यक्षीकरण → हैबियस कॉर्पस

"मैंडमस"

- किस रिट का उद्देश्य विधिपूर्ण कार्य करने से है, न कि अवैध कार्य → परमादेश

- कौन-सी रिट को तब जारी किया जाता है, जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्त्तव्य का पालन नहीं करता → परमादेश

- किस रिट के माध्यम से किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को अपने कर्त्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है → परमादेश
  "मैंडमस"
- किस रिट को किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है → परमादेश
- कर्त्तव्य का पालन करने का आदेश देने वाली किस रिट को निजी/ व्यक्तियों या इकाई के विरूद्ध जारी नहीं किया जा सकता है → परमादेश
  ↑ Private

- अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा किसने दी →
  डॉ. भीमराव अम्बेडकर

- अनुच्छेद 32 किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है →
  निलंबित → समाप्त
  (1) आपातकाल (2) सैन्य सदस्य (3) सैन्य विधि लागू हो

- व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है →
  स्वतंत्रता → शरीर → बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस)

- कर्त्तव्य का पालन करने का आदेश देने वाली किस रिट को भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के विरूद्ध जारी नहीं किया जा सकता → परमादेश।
- कर्त्तव्य का पालन करने का आदेश देने वाली किस रिट को न्यायिक क्षमता में कार्यरत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरूद्ध जारी नहीं किया जा सकता है → परमादेश।
- कौन-से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं → मूल अधिकारों के प्रवर्तन

- कर्त्तव्य का पालन करने का आदेश देने वाली किस रिट का गैर-संवैधानिक विभागों के विरूद्ध जारी नहीं किया जा सकता है → परमादेश।
  निजी व्यक्तियों, निजी इकाई
- कर्त्तव्य का पालन करने का आदेश देने वाली किस रिट को विवेकानुसार कर्त्तव्य नहीं होने पर जारी नहीं किया जा सकता है → परमादेश।
- कर्त्तव्य का पालन करने का आदेश देने वाली किस रिट को संविधात्मक दायित्व को लागू करने के विरूद्ध जारी नहीं किया जा सकता है → परमादेश।

Nitin Sir Hand Written E-Books

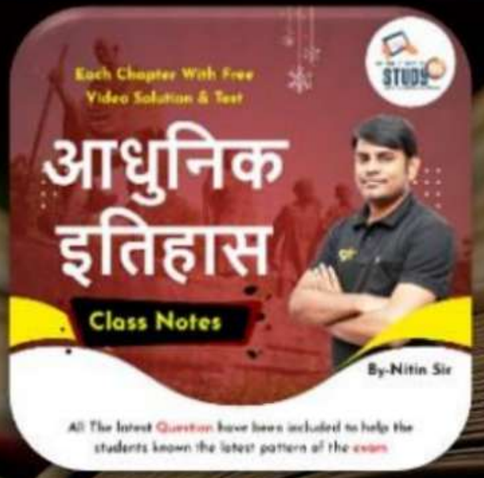

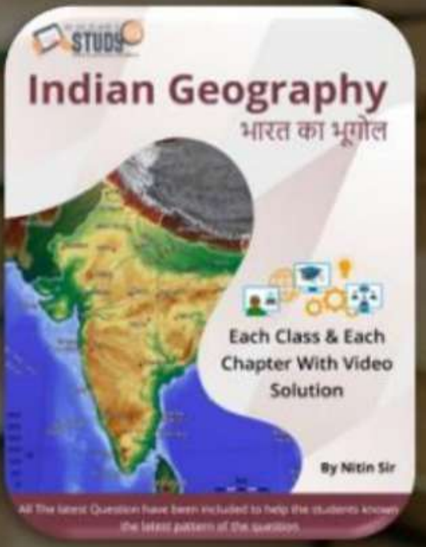

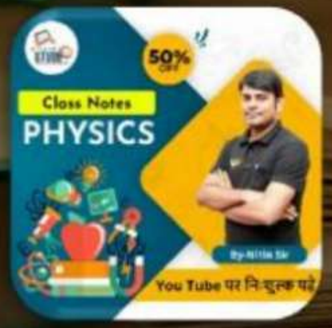

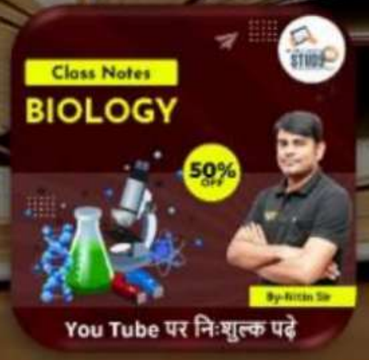

Thank You